प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
02.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00 बजे

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा पेश आम बजट ऐतिहासिक है और इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिम्ब झलकता है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवा शक्ति बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें अलग अलग सैक्टर्स में युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग को वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर 31 प्रतिशत तक करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29 दशमलव 5 प्रतिशत है, जिसे योजनाबद्ध और सतत तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है और इसके प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने देशी प्रजातियों, फलदार पौधों और औषधीय महत्व वाले पौधों के रोपण पर भी बल दिया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पौधरोपण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' शुरू की है। इस पहल में कुल 2 सौ 85 महिला मंडल, 70 युवक मंडल, 59 स्वयं सहायता समूह और 13 समुदाय आधारित संगठनों ने सक्रिय योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लोकसभा – बालिका शिक्षा

केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्तमान में सात लाख से अधिक छात्राएं अध्य यनरत हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से दो लाख से अधिक छात्राएं अनुसूचित जाति, एक लाख 77 हजार अनुसूचित जनजाति और दो लाख 64 हजार अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों के माध्यम से वंचित वर्गों की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 में सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की है।

पीएमजीएसवाई

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण चार के तहत शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्रों में सड़कों का जाल और मजबूत होगा। जिले में पीएमजीएसवाई चार के तहत केंद्र ने 92 नई सड़कें बनाने की स्वीकृति दी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट...

———————————